

गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार में गांवों के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान बनेगा। राज्य सरकार ने इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। मनरेगा कार्यों के माध्यम से मास्टर प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में योजनाओं के चयन में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यह घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने की।

श्री मिश्र सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित 'हमारा गांव-हमारा विकास' प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि



इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 293 प्रखंडों में आम लोगों की भागीदारी और उनकी सहमति से लेबर बजट बनाया जाएगा। शहरों की भांति गांवों का समग्र विकास करना है। सभी स्कीम के समन्वय से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी बीडीओ से कहा कि वे ऐसा मास्टर

प्लान बनाएं, जिसके सहारे अगले दस साल की कार्य योजना तय की जा सके। सही स्कीम का चयन हो। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एसएम राजू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगले पांच साल में शहरों के समान सभी बुनियादी सुविधाएं देनी हैं।

- राज्य के 293 प्रखंडों में बनेगा लेबर बजट
- पांच साल में गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं
- पश्चिम चंपारण का गोनहा विकास का रोल मॉडल